सीमाशुल्क(अपील) आयुक्तकाकार्यालय,

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (APPEALS), अहमदाबाद AHMEDABAD,

चौथी मंज़िल 4th Floor, हडकोभवनHUDCO Bhavan, ईश्वर भुवन रोड़ IshwarBhuvan Road,

नवरंगपुरा Navrangpura, अहमदाबाद Ahmedabad – 380 009

दूरभाषक्रमांक Tel. No. 079-26589281

DIN - 20250971MN000000E9DC

क	फ़ाइल संख्या FILE NO.	S/49-148/CUS/JMN/2025-26
ख	अपील आदेश संख्या ORDER-IN-APPEAL NO. (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 128क के अंतर्गत) (UNDER SECTION 128A OF THE CUSTOMS ACT, 1962):	JMN-CUSTM-000-APP-300-25-26
ग	पारितकर्ता PASSED BY	Shri Amit Gupta Commissioner of Customs (Appeals), Ahmedabad
घ	दिनांक DATE	12.09.2025
ङ	उदभूत अपील आदेश की सं. व दिनांक ARISING OUT OF ORDER-IN-ORIGINAL NO.	263/CUS-REF/2024-25 dated 30.07.2024
च	अपील आदेश जारी करने की दिनांक ORDER- IN-APPEAL ISSUED ON:	12.09.2025
छ	अपीलकर्ता का नाम व पता NAME AND ADDRESS OF THE APPELLANT:	M/s Malwi Ship Breaking Co., Plot No 58 (24 D), Ship Recycling Yard, Alang, Dist – Bhavnagar.

1.	यह प्रति उस व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए मुफ्त में दी जाती है जिनके नाम यह जारी किया गया है.
	This copy is granted free of cost for the private use of the person to whom it is issued.
2.	सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129 डी डी (1) (यथा संशोधित) के अधीन निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति इस आदेश से अपने को आहत महसूस करता हो तो इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के अंदर अपर सचिव/संयुक्त सचिव (आवेदन संशोधन), वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) संसद मार्ग, नई दिल्ली को पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर

	सकते है.
	Under Section 129 DD(1) of the Customs Act, 1962 (as amended), in respect of the following categories of cases, any person aggrieved by this order can prefer a Revision Application to The Additional Secretary/Joint Secretary (Revision Application), Ministry of Finance, (Department of Revenue) Parliament Street, New Delhi within 3 months from the date of communication of the order.
	निम्नलिखित सम्बन्धित आदेश/Order relating to :
(क)	बैगेज़ के रूप में आयातित कोई माल.
(a)	any goods imported on baggage.
(ख)	भारत में आयात करने हेतु किसी वाहन में लादा गया लेकिन भारत में उनके गन्तव्य स्थान पर उतारे न गए माल या उस गन्तव्य स्थान पर उतारे जाने के लिए अपेक्षित माल उतारे न जाने पर या उस गन्तव्य स्थान पर उतारे गए माल की मात्रा में अपेक्षित माल से कमी हो.
(b)	any goods loaded in a conveyance for importation into India, but which are not unloaded at their place of destination in India or so much of the quantity of such goods as has not been unloaded at any such destination if goods unloaded at such destination are short of the quantity required to be unloaded at that destination.
(ग)	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय X तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत शुल्क वापसी की अदायगी.
(c)	Payment of drawback as provided in Chapter X of Customs Act, 1962 and the rules made thereunder.
3.	पुनरीक्षण आवेदन पत्र संगत नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा जिसके अन्तर्गत उसकी जांच की जाएगी और उस के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न होने चाहिए :
	The revision application should be in such form and shall be verified in such manner as may be specified in the relevant rules and should be accompanied by :
(क)	कोर्ट फी एक्ट,1870 के मद सं.6 अनुसूची 1 के अधीन निर्धारित किए गए अनुसार इस आदेश की 4 प्रतियां, जिसकी एक प्रति में पचास पैसे की न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए.
(a)	4 copies of this order, bearing Court Fee Stamp of paise fifty only in one copy as prescribed under Schedule 1 item 6 of the Court Fee Act, 1870.
(ख)	सम्बद्ध दस्तावेज़ों के अलावा साथ मूल आदेश की 4 प्रतियां, यदि हो
(b)	4 copies of the Order-in-Original, in addition to relevant documents, if any
(ग)	पुनरीक्षण के लिए आवेदन की 4 प्रतियां
(c)	4 copies of the Application for Revision.
(घ)	पुनरीक्षण आवेदन दायर करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) में निर्धारित फीस जी अन्य रसीद, फीस,दण्ड,जब्ती और विविध मदों के शीर्ष के अधीन आता है में रु. 200/-(रूपए दो सौ मात्र)या रु.1000/- (रूपए एक हज़ार मात्र), जैसा भी मामला हो, से सम्ब न्धित भुगतान के प्रमाणिक चलान टी.आर.6 की दो प्रतियां. यदि शुल्क, मांगा गया ब्याज, लगाया गया दंड की राशि और रूपए एक लाख या उससे कम हो तो ऐसे फीस के रूप में रु.200/- और यदि एक लाख से अधिक हो तो फीस के रूप में रु.1000/-
(d)	The duplicate copy of the T.R.6 challan evidencing payment of Rs.200/- (Rupees two Hundred only) or Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only) as the case may be, under the Head of other receipts, fees, fines, forfeitures and Miscellaneous Items being the fee prescribed in the Customs Act, 1962 (as amended) for filing a Revision Application. If the amount of duty and interest demanded, fine or penalty levied is one lakh rupees or less, fees as Rs.200/- and if it is more than one lakh rupees, the fee is Rs.1000/-.
4.	मद सं. 2 के अधीन सूचित मामलों के अलावा अन्य मामलों के सम्बंन्ध में यदि कोई व्यक्ति इस आदेश से आहत महसूस करता हो तो वे सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129 ए (1) के अधीन फॉर्म सी.ए.-3 में सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं
	In respect of cases other than these mentioned under item 2 above, any person aggrieved by this order can file an appeal under Section 129 A(1) of the Customs Act, 1962 in form C.A.-3 before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal at the following address :
	सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलिय अधिकरण, पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ — **Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, West Zonal Bench**
	दूसरी मंज़िल, बहुमाली भवन, निकट गिरधरनगर पुल, असारवा, अहमदाबाद-380016 — 2nd Floor, Bahumali Bhavan, Nr.Girdhar Nagar Bridge, Asarwa,

		Ahmedabad-380 016
5.	**सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 ए (6) के अधीन, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 ए (1) के अधीन अपील के साथ निम्नलिखित शुल्क संलग्न होने चाहिए-**	
	Under Section 129 A (6) of the Customs Act, 1962 an appeal under Section 129 A (1) of the Customs Act, 1962 shall be accompanied by a fee of -	
(क)	**अपील से सम्बन्धित मामले में जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगा गया शुल्क और व्याज तथा लगाया गया दंड की रकम पाँच लाख रूपए या उससे कम हो तो एक हज़ार रुपए.**	
(a)	where the amount of duty and interest demanded and penalty levied by any officer of Customs in the case to which the appeal relates is five lakh rupees or less, one thousand rupees;	
(ख)	**अपील से सम्बन्धित मामले में जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगा गया शुल्क और व्याज तथा लगाया गया दंड की रकम पाँच लाख रूपए से अधिक हो लेकिन रुपये पचास लाख से अधिक न हो तो; पांच हज़ार रुपए**	
(b)	where the amount of duty and interest demanded and penalty levied by any officer of Customs in the case to which the appeal relates is more than five lakh rupees but not exceeding fifty lakh rupees, five thousand rupees ;	
(ग)	**अपील से सम्बन्धित मामले में जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगा गया शुल्क और व्याज तथा लगाया गया दंड की रकम पचास लाख रूपए से अधिक हो तो; दस हज़ार रुपए.**	
(c)	where the amount of duty and interest demanded and penalty levied by any officer of Customs in the case to which the appeal relates is more than fifty lakh rupees, ten thousand rupees	
(घ)	इस आदेश के विरुद्ध अधिकरण के सामने, मांगे गए शुल्क के 10% अदा करने पर, जहां शुल्क या शुल्क एवं दंड विवाद में हैं, या दंड के 10% अदा करने पर, जहां केवल दंड विवाद में है, अपील रखा जाएगा ।	
(d)	An appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute.	
6.	**उक्त अधिनियम की धारा 129 (ए) के अन्तर्गत अपील प्राधिकरण के समक्ष दायर प्रत्येक आवेदन पत्र- (क) रोक आदेश के लिए या गलतियों को सुधारने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किए गए अपील : - अथवा (ख) अपील या आवेदन पत्र का प्रत्यावर्तन के लिए दायर आवेदन के साथ रुपये पाँच सौ का शुल्क भी संलग्न होने चाहिए.**	
	Under section 129 (a) of the said Act, every application made before the Appellate Tribunal- (a) in an appeal for grant of stay or for rectification of mistake or for any other purpose; or (b) for restoration of an appeal or an application shall be accompanied by a fee of five Hundred rupees.	

ORDER-IN-APPEAL

M/s Malwi Ship Breaking Co., Plot No 58 (24 D), Ship Recycling Yard, Alang, Dist – Bhavnagar (hereinafter referred to as "the appellant") have filed an appeal in terms of Section 128 of the Customs Act, 1962 against the Order-in-Original No. 263/CUS-REF/2024-25 dated 30.07.2024 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by the Assistant Commissioner, Customs Division, Bhavnagar (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

2. Briefly stated, facts of the case are that the appellant, having their Ship Recycling Yard at Plot No 58 (24 D), Ship Recycling Yard, Alang, Dist – Bhavnagar, had imported one vessel MV FRIO ATHENS for breaking up/recycling and filed Bill of Entry No. 7150579, dated 10.07.2018 under Section 46 of the Customs Act, 1962. They had self-assessed the goods viz. Vessels for breaking under CTH 89.08, Bunkers under CTH 27.10 & Consumables under CTH 98.05 and paid the assessed customs duty.

2.1 There were some dispute with regard to assessment of customs duty on the Fuel and Oil (Fuel Oil, Marine Gas Oil, Lub. Oil) contained in Bunker Tanks inside/outside the engine room of the vessel. The appellant claimed that Fuel and Oil contained in Bunker Tanks inside/outside the engine room of the vessel was to be assessed to duty under CTSH 89.08 along with the vessel. The Department was of the view that Fuel and Oil contained in Bunker Tanks were to be assessed to duty under respective CTH i.e., Chapter 27. Thereafter, the subject Bill of Entry was assessed provisionally for want of original documents.

2.2 Further, Hon'ble CESTAT, Ahmedabad, vide its Order No. A/11792-11851/2022, dated 17.10.2022/01.12.2022 had held that the oil contained in the Bunkers Tanks in the engine room of the vessel is to be assessed to duty under CTH 8908, along with the vessel for breaking up. Further, in view of the aforesaid order of the Hon'ble CESTAT, the Assistant Commissioner, Customs Division, Bhavnagar vide Final Assessment Order No. 51/2439141/SBY/2023-24, dated 30.08.2023 held that Bunker Tanks containing oil are to treated as part of vessel's machinery and the Oils contained in them are to be classified under CTH 8908 along with the vessel, as covered under Para 2(b) of Circular No 37/96 – Cus, dated 03.07.1996. The Bill of Entry was finally assessed vide Final Assessment Order No. 51/2439141/SBY/2023-24, dated 30.08.2023 passed by the Assistant Commissioner, Customs Division, Bhavnagar. Consequently, the appellant had filed refund claim which was decided vide the impugned order.

2.3 The adjudicating authority observed that the appellant has submitted a copy of Certificate dated 10.01.2024 issued by CA M/s SSM & Co., wherein it is stated that the incidence of Customs duty paid on Bunker (oil and fuel) have not been passed on to any other person. The appellant was requested to produce C.A. Certificate in the format provided along with the documentary evidence to verify that the refund amount claimed were shown as 'amount receivable' in the books of account and that the incidence of duty (claimed as refund) had not been passed on to any other person. The appellant submitted that unjust enrichment is not applicable in their case and relied upon following case laws: -

(i) 2017 (348) E.L.T. 537 (Tri. -Chennai)

(ii) 2015 (327) E.L.T. 13 (Mad)

(iii) 2018 (360) E.L.T. A 204 (Bom)

(iv) 2020 (371) E.L.T. 542 (Chan)

(v) 2022(60) G.S.T.L. 48 (Del).

2.4 The adjudicating authority found that the case laws cited by the claimant were not relevant in the issue as far as clause of unjust enrichment is concerned. The adjudicating authority also found that that when the element of any duty paid on any goods is debited to Purchase Account which is forming part of the Profit & Loss Account, as a cardinal accounting principles, the said element of duty becomes a part of the cost of the goods. As such, whenever such goods are sold at a later stage to the buyers/ customers, the Sales Price fetched for such goods is considered as inclusive of the element of duty paid thereon such goods. Accordingly, here in the case, it was observed that the incidence of Customs duty paid at the time of import of goods is passed on to the buyers/ customers at the time of its sales in the form of Sales Price. The adjudicating authority also observed that once the amount of Customs Duty paid is debited as cost to purchase under Profit & Loss Account and non-fulfillment of obligatory condition of Section 28C would be sufficient enough to conclude that Sales Price of the goods bear entire Customs Duty paid on such goods. Under such circumstances, the grant of refund of Customs Duty would tantamount to receipt of refund of customs duty from customers as well as from exchequer, which will get the claimant unjustly enriched. Thereafter, the adjudicating authority relying upon the Final Order No. A/30122-30123/2023, dated 01.06.2023 passed by the Hon'ble CESTAT, Hyderabad in the case of Sachdev Overseas Fitness Pvt. Ltd & Nityasach Fitness Pvt. Ltd has sanctioned the refund claim of Rs 7,86,009/- in terms of Section

27 of the Customs Act, 1962 and credited the same to the Consumer Welfare Fund.

3. Being aggrieved with the impugned Order, the appellant has filed the present appeal contending on grounds as mentioned in the grounds of appeal.

4. Shri Rahul Gajera, Advocate, appeared for personal hearing on 07.08.2025 on behalf of the appellant. He reiterated the written submission made at the time of filing appeal.

5. Before going into the merits of the case, it is observed that the date of communication of the impugned order as per appeal memorandum is 02.08.2024 and the present appeal was filed on 23.06.2025, i.e., after 325 days. In this regard, I have gone through the provision of limitations for filing an appeal as specified under Section 128(1) of the Customs Act, 1962. The same is reproduced hereunder:

> *"SECTION 128. Appeals to [Commissioner (Appeals)]. — (1) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act by an officer of customs lower in rank than a [Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs] may appeal to the [Commissioner (Appeals)] [within sixty days] from the date of the communication to him of such decision or order.*
>
> *[Provided that the Commissioner (Appeals) may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of sixty days, allow it to be presented within a further period of thirty days.]"*

5.1 As per the legal provisions under Section 128 of the Customs Act, 1962, the appeal has to be filed within 60 days from the date of communication of order. Further, if the Commissioner (Appeals) is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of 60 days, he can allow it to be presented within a further period of 30 days.

5.2 It will also be relevant to refer to the judgment of Hon'ble Supreme Court in case of Singh Enterprises – [2008 (221) E.L.T. 163 (S.C.)], wherein the Hon'ble Apex Court had, while interpreting the Section 35 of the Central Excise Act, 1944, which is pari materia to Section 128 of the Customs Act, 1962, held that the appeal has to be filed within 60 days, but in terms of the proviso, further 30 days' time can be granted by the appellate authority to entertain the appeal. The proviso to sub-section (1) of Section 35 makes the position crystal clear that the appellate authority has

no power to allow the appeal to be presented beyond the period of 30 days. The relevant para is reproduced below:

> ***"8.*** *The Commissioner of Central Excise (Appeals) as also the Tribunal being creatures of Statute are vested with jurisdiction to condone the delay beyond the permissible period provided under the Statute. The period upto which the prayer for condonation can be accepted is statutorily provided. It was submitted that the logic of Section 5 of the Indian Limitation Act, 1963 (in short the 'Limitation Act') can be availed for condonation of delay. The first proviso to Section 35 makes the position clear that the appeal has to be preferred within three months from the date of communication to him of the decision or order. However, if the Commissioner is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of 60 days, he can allow it to be presented within a further period of 30 days. In other words, this clearly shows that the appeal has to be filed within 60 days but in terms of the proviso further 30 days time can be granted by the appellate authority to entertain the appeal. The proviso to sub-section (1) of Section 35 makes the position crystal clear that the appellate authority has no power to allow the appeal to be presented beyond the period of 30 days. The language used makes the position clear that the legislature intended the appellate authority to entertain the appeal by condoning delay only upto 30 days after the expiry of 60 days which is the normal period for preferring appeal. Therefore, there is complete exclusion of Section 5 of the Limitation Act. The Commissioner and the High Court were therefore justified in holding that there was no power to condone the delay after the expiry of 30 days period."*

5.3 The above view was reiterated by the Hon'ble Supreme Court in Amchong Tea Estate [2010 (257) E.L.T. 3 (S.C.)]. Further, the Hon'ble High Court of Gujarat in case of Ramesh Vasantbhai Bhojani – [2017 (357) E.L.T. 63 (Guj.)] and Hon'ble Tribunal Bangalore in the case of Shri Abdul Gafoor Vs Commissioner of Customs (Appeals) [2024-TIOL-565-CESTAT-BANG] took a similar view while dealing with Section 128 of the Customs Act, 1962.

5.4 In terms of legal provisions under Section 128 of the Customs Act, 1962 and in light of the judicial pronouncements by the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court and Hon'ble Tribunal Bangalore, it is settled

proposition of law that the appeals before first appellate authority are required to be filed within 90 days, including the condonable period of 30 days as provided in the statute, and the Commissioner (Appeals) is not empowered to condone any delay beyond 30 days.

5.5 In light of the above observation, I find that the appeal has been filed after 90 days from the date of receipt of the order. I am not empowered to condone the delay in filing the appeal beyond the period specified in Section 128 of the Customs Act, 1962. Hence, the same is held to be time barred.

6. In view of above, I reject appeal on the grounds of limitation without going into the merits of the case.

(AMIT GUPTA)
COMMISSIONER (APPEALS)
CUSTOMS, AHMEDABAD.

By Registered Post A.D.

F. Nos. S/49-148/CUS/JMN/2025-26/3405 Dated – 12.09.2025

To,

1. M/s Malwi Ship Breaking Co.,
   Plot No 58 (24 D), Ship Recycling Yard,
   Alang, Dist – Bhavnagar,

Copy to:

1. The Chief Commissioner of Customs Gujarat, Customs House, Ahmedabad.
2. The Commissioner of Customs, Customs, Jamnagar.
3. The Assistant/Deputy Commissioner of Customs, Customs Division, Bhavnagar.
4. Guard File

सत्यापित/ATTESTED
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
सीमा शुल्क (अपील), अहमदाबाद.
CUSTOMS (APPEALS), AHMEDABAD.